जयपुर भाजपा के टिकटों में महिलाओं व मुस्लिम पर जोर

नई रणनीति के तहत भाजपा की 145 प्रत्याशियों की सूची में 52 महिलाएं, 8 मुस्लिम

■ माना जा रहा है, भाजपा ने महिला नेतृत्व को चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बनाया है। आरक्षित सीटों के अलावा भी कई सामान्य व महत्वपूर्ण वॉर्डों में महिला चेहरों को उतारा गया है।

जयपुर, 31 अगस्त। नगर निगम चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही, अपने सियासी समीकरण भी साफ कर दिए हैं। पार्टी की ओर से जारी 145 प्रत्याशियों की सूची में 52 महिलाओं और 8 मुस्लिम चेहरों को मौका दिया गया है। टिकट वितरण में महिला प्रतिनिधित्व के साथ अल्पसंख्यक समाज को जगह देकर भाजपा ने सामाजिक संतुलन साधने और अपने राजनीतिक आधार का विस्तार करने का संदेश दिया है।

भाजपा की इस सूची में मुस्लिम समाज के आठ प्रत्याशी शामिल हैं। इनमें वार्ड 19 से शहनवाज अंसारी, वार्ड 109 से जाकिर खान कायमखानी, वार्ड 113 से फरीदुद्दीन 'जैकी', वार्ड 117 से शब्बो जहां, वार्ड 128 से माजिद पठान, वार्ड 136 से मिजाना मिर्जा, वार्ड 137 से रहीस मंसूरी और वार्ड 146 से अफसाना शामिल हैं। इनमें वार्ड 19 जैसी सामान्य सीट से शहनवाज अंसारी को टिकट मिलना राजनीतिक रूप से खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भाजपा ने 145 घोषित प्रत्याशियों में 52 महिलाओं को टिकट देकर महिला नेतृत्व को चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बनाया है। पार्टी की सूची में आरक्षित सीटों के साथ-साथ, कई सामान्य और महत्वपूर्ण वॉर्डों में भी महिला चेहरों को मैदान में उतारा गया है।

पार्टी की रणनीति में महिला प्रतिनिधित्व को केवल आरक्षण तक सीमित रखने के बजाय, महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका में आगे बढ़ाने का संदेश दिखाई दे रहा है। स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और परिवार स्तर पर उनके प्रभाव को देखते हुए, यह रणनीति भाजपा के लिए चुनावी रूप से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

भाजपा के मुस्लिम प्रत्याशियों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा उन सीटों पर है, जहां पार्टी ने सामान्य वार्डों में भी मुस्लिम चेहरों पर भरोसा जताया है। वार्ड 19 इसका प्रमुख उदाहरण है। इससे संकेत मिल रहा है कि भाजपा मुस्लिम मतदाताओं के बीच भी अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने और नए सामाजिक समूहों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है।

जयपुर नगर निगम चुनाव में अब प्रत्याशियों के नाम सामने आने के बाद मुकाबला और रोचक हो गया है। भाजपा के सामने अब टिकट वितरण के जरिए बनाए गए सामाजिक समीकरणों को वोट में बदलने की चुनौती होगी। महिला नेतृत्व, मुस्लिम प्रतिनिधित्व और जिताऊ चेहरों के सहारे भाजपा ने चुनावी मैदान में अपनी रणनीति का संकेत तो दे दिया है, अब इन समीकरणों की असली परीक्षा मतदान के दिन होगी।

कुशीनगर में नेपाल से बहकर आये 13 शव मिले

कुशीनगर, 31 अगस्त। नेपाल में आई भीषण बाढ़ की तबाही का असर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में भी दिखाई दे रहा है। नेपाल से निकलने वाली नारायणी नदी (भारत में गंडक नदी) कुशीनगर में इन दिनों उफान पर है।

नदी की तेज धारा में नेपाल से बहकर आये शव कुशीनगर तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में मृत पशु और अन्य सामान भी नदी में बहकर आ रहा है। जिला प्रशासन के मुताबिक,

■ बड़ी संख्या में मृत पशु और अन्य सामान भी नदी में बहकर आया।

गंडक नदी से अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं।

शवों की बरामदगी के लिए प्रशासन की निगरानी में एसडीआरएफ की टीम नदी और आसपास के क्षेत्रों में लगातार अभियान चला रही है। नदी की तेज धारा और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच रेस्क्यू टीम को अभियान के दौरान विशेष सावधानी बरतनी पड़ रही है। प्रशासन ने नदी क्षेत्र में निगरानी भी बढ़ा दी है।

दिल्ली में स्लीपर बस में 16 वर्षीय छात्रा के साथ गैंगरेप

परी चौक से कश्मीरी गेट, 47 किलोमीटर के बीच बस ड्राइवर व कंडक्टर ने हैवानियत की, दोनों गिरफ्तार

■ परिजनों से नाराज होकर छात्रा नोएडा अपने चचेरे भाई के पास जा रही थी गलती से ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर उतर गई।

नई दिल्ली, 31 अगस्त। राजधानी दिल्ली में एक और निर्भया कांड सामने आया है। एक स्लीपर बस में 16 वर्षीय छात्रा के साथ कथित तौर पर गैंगरेप की घटना हुई। परी चौक से कश्मीरी गेट की 47 किलोमीटर की दूरी के दौरान दो आरोपियों ने छात्रा के साथ हैवानियत की। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है।

यह घटना कश्मीरी गेट इलाके में 4 अगस्त की रात को हुई थी। फिलहाल, मामले में पुलिस ने बस के ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप को गिरफ्तार किया है। पीड़िता उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की रहने वाली है और 11वीं कक्षा की छात्रा है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, छात्रा परिजनों से नाराज होकर बिना बताए घर से निकल गई थी और नोएडा में रहने वाले अपने चचेरे भाई के पास जा रही थी। भारी बारिश और अंधेरे के कारण छात्रा गलती से ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर उतर गई। इसी दौरान एक खाली स्लीपर बस वहां से गुजरी। छात्रा ने बस को रुकने का इशारा किया, जिसके बाद बस रुक गई। ड्राइवर-कंडक्टर ने उसे नोएडा सेक्टर-63 जाने की बात कहकर बस में बैठा लिया।

आरोप है कि बस चलने के कुछ देर बाद कंडक्टर ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकत शुरू कर दी। पीड़िता के मुताबिक, इसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर ने उसके साथ रेप किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी पीड़िता को देर रात कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास रिंग रोड पर उतारकर फरार हो गए।

घबराई हुई छात्रा ने कश्मीरी गेट पुलिस से संपर्क कर पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को तिमारपुर की एक बस पार्किंग से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल स्लीपर बस को जब्त कर लिया है और उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी बस में खराबी आने के बाद बस को सूरजपुर की वर्कशॉप में रिपेयरिंग के लिए लेकर गए थे। बस की रिपेयरिंग के बाद ड्राइवर और कंडक्टर खाली बस लेकर तिमारपुर जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर छात्रा मिली। परी चौक से कश्मीरी गेट तक करीब 47 किलोमीटर का सफर बस ने तय किया। बस स्लीपर होने और पर्दे लगे होने के कारण किसी भी राहगीर को बस के अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया था।

सीजेपी के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि इस स्तर पर अदालत यह अनुमान नहीं लगा सकती कि दिल्ली में सीजेपी के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, कम से कम अभी हम यह मानकर चलेंगे और हमारे पास इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि हर व्यक्ति बहुत जिम्मेदारी और शांतिपूर्ण तथा कानूनसम्मत तरीके से व्यवहार करेगा। इसलिए फिलहाल हमारे सामने ऐसी कोई बाध्यकारी परिस्थिति नहीं है, जिससे यह मान लिया जाए कि कुछ गलत होगा।

अदालत ने याचिका दायर करने वाले व्यक्ति से कहा कि संभावित कानून-व्यवस्था की समस्याओं को लेकर अपनी शिकायतों और आशंकाओं के संबंध में वह केन्द्र सरकार से संपर्क करे।

सीजेपी ने 5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक शांतिपूर्ण मार्च का आव्हान किया है। यह मार्च केन्द्र सरकार द्वारा 25 जुलाई को दिए गए आश्वासनों को कथित रूप से पूरा न किए जाने के विरोध में आयोजित किया जा रहा है। इनमें विशेष रूप से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का आश्वासन शामिल है।

बम की धमकी के बाद एयर इंडिया विमान ने अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग की

सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। विमान, यात्रियों के सामान व कार्गो क्षेत्र की गहन जांच हुई

■ पुलिस के अनुसार फ्लाइट के बाथरुम में मेम्बर को कागज का एक टुकड़ा मिला, जिस पर 'बम' लिखा हुआ था। सुरक्षा प्रोटोपॉल के तहत तुरंत कार्यवाही करते हुए विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई।

अहमदाबाद, 31 अगस्त। सऊदी अरब के दम्माम से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट को बम की धमकी मिलने के बाद अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।

धमकी मिलने के बाद फ्लाइट को तत्काल अहमदाबाद की ओर डायवर्ट किया गया। फ्लाइट के एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से उतरने के बाद उसे आइसोलेशन बे में खड़ा किया गया। विमान में सवार सभी 32 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर विशेष बसों के जरिए एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 में पहुंचाया गया।

घटना की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। मौके पर फायर विभाग की तीन गाड़ियां, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और बम डिस्पोजल एंड डिटेक्शन स्क्वॉड (बीडीडीएस) की टीम पहुंची। विमान के अलावा, यात्रियों के सामान और कार्गो क्षेत्र की भी गहन जांच की गई।

पुलिस के अनुसार, फ्लाइट के बाथरूम से क्रू मेंबर को कागज का एक टुकड़ा मिला, जिस पर 'बम' लिखा हुआ था। इसके बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत तत्काल कार्रवाई करते हुए विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। प्राथमिक जांच में विमान से इसके अलावा कोई संदिग्ध या आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है। इसके बावजूद सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं। धमकी किसने और किस उद्देश्य से दी, इसका पता लगाने के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। पुलिस ने बताया कि फिलहाल सभी यात्रियों को सुरक्षित टर्मिनल-2 में रखा गया है और विमान की जांच जारी है। घटना के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

पहली तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली, 31 अगस्त। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8 प्रतिशत बढ़ी है। इससे साल की शुरुआत उम्मीद से बेहतर रही। मुश्किल ग्लोबल माहौल के बावजूद, अर्थव्यवस्था में मजबूती बनी रही। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए इन्हें शानदार बताया है।

अप्रैल-जून की ग्रोथ का आंकड़ा अर्थशास्त्रियों के अनुमान (लगभग 7.1 प्रतिशत) से काफी ज्यादा रहा। जीडीपी

■ यह बढ़ोतरी अर्थशास्त्रियों के अनुमान से कही अधिक है।

की नई सीरीज के तहत, पिछले साल इसी तिमाही में अर्थव्यवस्था 6.9 प्रतिशत बढ़ी थी। इसलिए ताजा आंकड़ा एक उल्लेखनीय सुधार दिखाता है।

ये ताजा आंकड़े जियो-पॉलिटिकल टेंशन, ऊर्जा की ऊंची कीमतों और ग्लोबल ट्रेड को लेकर अनिश्चितता के माहौल में आए हैं। इन दबावों के बावजूद, घरेलू मांग आर्थिक गतिविधि के लिए मुख्य सहारा बनी रही तथा सरकारी कैपिटल खर्च, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और एक्सपोर्ट ने भी ग्रोथ में योगदान दिया।

टाटा भारत में टैंक रोधी मिसाइल जैवलिन बनायेगा

■ टाटा एडवांस्ड सिस्टम तथा जैवलिन जॉइंट वैंचर ने समझौते पर हस्ताक्षर किये।

नई दिल्ली, 31 अगस्त। भारत ने अमेरिका से टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली एफजीएम-148 जैवलिन खरीदने का समझौता किया है।

भारत ने जैवलिन प्रणाली के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। अब टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और जैवलिन जॉइंट वेंचर (जेजेवी) ने भारत में इस प्रणाली के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। यह करार भारतीय रक्षा उद्योग को खास मौके देगा और इंडो-पैसिफिक के लिए क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करेगा।

अमेरिकी राजदूतावास की प्रवक्ता डाना जिए ने 28 अगस्त को पुष्टि की थी कि भारत ने जैवलिन प्रणाली के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस समझौते पर हस्ताक्षर के साथ भारत जैवलिन प्रणाली का ग्राहक बन गया है, जो एक उन्नत, मध्यम दूरी की फायर-एंड-फॉरगेट एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल है।

अब भारत में जैवलिन प्रणाली के निर्माण के लिए जैवलिन जॉइंट वेंचर ने टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स को प्राइम पार्टनर के तौर पर चुना है। इस करार के तहत, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और जेजेवी भारत में जैवलिन प्रणाली के लिए एक फाइनल असेंबली और एकीकरण सुविधा बनाने के बारे में पता लगाएंगे।

टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली एफजीएम-148 जैवलिन भारत और अमेरिकी पार्टनरशिप के लिए फायदेमंद होगी। इससे भारत में एक मजबूत डिफेंस वर्कफोर्स बनेगी। साथ ही कई साल के प्रोडक्शन के जरिए घरेलू सप्लाई चेन में अमेरिकी नौकरियां बनी रहेंगी। देश में को-प्रोडक्शन शुरू होने से भारत का डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस मजबूत होगा। इससे जैवलिन की फाइनल असेंबली और इंटीग्रेशन भारतीय फैसिलिटी और सप्लायर तक पहुंचेंगे, हाई-टेक नौकरियां पैदा होंगी, स्थानीय विनिर्माण विशेषज्ञता बढ़ेगी।

उत्तर प्रदेशः पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 11 की मौत

प्रयागराज, 31 अगस्त। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पड़ोसी जिले कौशाम्बी के पिपरी थाना क्षेत्र में सोमवार को एक पटाखा फैक्टरी में हुए भीषण विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। मरने वाले 11 लोगों में से 8 बच्चे हैं। घायलों को स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय समेत, प्रयागराज के अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

कौशांबी के पुलिस अधीक्षक सत्य नारायण प्रजापत के मुताबिक, मामले में

■ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रु. की आर्थिक सहायता की घोषणा की।

आदिल समेत, छह लोगों के खिलाफ पिपरी थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की चार टीमें गठित की गई हैं। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

दिल्ली में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कर दिए गए हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सूची से बाहर किए गए मतदाता 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के जरिए अपने दावे पेश कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को जारी की जाएगी।

संशोधित चुनाव आयोग कार्यक्रम के अनुसार, दावों और आपत्तियों की जांच की जाएगी तथा नोटिस जारी करने और उनके निपटारे की प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक चलेगी।

प्रारूप मतदाता सूची में करीब 97.5 लाख मतदाताओं को शामिल किया गया है, जिनके गणना फॉर्म घर-घर जाकर किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इन्टेन्सिव रिवीज़न -एसआईआर) के दौरान प्राप्त हुए और डिजिटाइज़ किए गए।

यह अभियान 30 जून को शुरू हुआ था और 17 अगस्त को समाप्त हुआ। इस प्रक्रिया के दौरान, दिल्ली के कुल 1,45,10,299 मतदाताओं में से करीब 67.18 प्रतिशत के फॉर्म डिजिटाइज़ किए गए।

शेष 47.7 लाख मतदाताओं को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, दोहरे या अन्य श्रेणी में "अप्राप्य" माना गया और उनके नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए। शहर की 70 विधानसभा सीटों में डिजिटाइज़ेशन की दर में काफी अंतर रहा। रोहिणी में सबसे अधिक 83.43 प्रतिशत फॉर्म डिजिटाइज़ किए गए, जबकि तुगलकाबाद में यह दर सबसे कम 52.15 प्रतिशत रही।

संजय के. अग्रवाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

न्यायिक क्षेत्र के लोग इस तबादला आदेश को वर्तमान एक्टिंग सीजे एस.पी. शर्मा से जुड़े हालिया विवाद के साथ सीधे तौर पर जोड़कर देख रहे हैं। माना जा रहा है कि इस फेरबदल के जरिए सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के प्रशासनिक संतुलन और न्यायिक व्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करना चाहता है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जज संदीप मेहता ने सीजीआई सूर्यकांत से राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे एस.पी. शर्मा को राजस्थान हाई कोर्ट से ट्रांसफर करने की गुहार की थी और उनके स्थान पर दूसरे जज को लगाने की भी मांग की थी।

इसके बाद सीजीआई का भी बयान सामने आया था कि मामले की उच्च स्तर पर जांच कर प्रकरण के सभी पहलुओं को देखने के बाद ही किसी तरह का निर्णय लिया जाएगा। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा आगामी 26 सितम्बर को रिटायर हो रहे हैं।

नेपाल में अब तक 903 शव मिले

काठमांडू, 31 अगस्त। नेपाल के रसुवा में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद, राहत, खोज और बचाव अभियान लगातार जारी है। नेपाल के गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की

■ नेपाल के अनुसार, अभी 4247 लोग लापता हैं।

आज सुबह 11 बजे तक की रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक 903 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 4,247 लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों में जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े 933 लोग, मकवानपुर के 65, विदेशी नागरिक 592, विदेशियों के साथ यात्रा कर रहे 127 नेपाली नागरिक, लैंगटांग राष्ट्रीय उद्यान के 3 और क्वारंटीन कार्यालय के 3 लोग भी शामिल हैं। नेपाल सरकार के मुताबिक, अब तक कुल 10,451 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है।

भारत ने सिंधु जल संधि पर ऑबिट्रेशन के फैसले को खारिज किया

नई दिल्ली, 31 अगस्त। अंतरराष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता करने वाले हेग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (पीसीए) की तरफ से सिंधु जल संधि पर सुनाये गये फैसले को भारत सरकार ने एक सिरे से खारिज कर दिया है।

पाकिस्तान की अपील पर पीसीए ने सोमवार को सिंधु जल संधि पर फैसले सुनाये हैं। एक फैसला उक्त संधि की स्थिति को लेकर है, जबकि दूसरा यह है कि क्या दोनों में से कोई एक देश इस संधि को खारिज कर सकता है।

अदालत ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पूरी तरह लागू है और भारत को संधि के तहत अपनी बाध्यताओं का पालन करना चाहिए। अदालत ने भारत के संधि को स्थगित रखने के फैसले को संधि को निलंबित या समाप्त करने के प्रयास के रूप में देखा है और कहा कि संधि, किसी एक पक्ष को इसे समाप्त, निलंबित या स्थगित करने का अधिकार नहीं देती। कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में रतले जलविद्युत परियोजना पर कुछ निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक लगाने का भी निर्देश दिया है।

पीसीए के फैसले को एक सिरे से खारिज करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कहा है कि यह तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय, विश्व बैंक द्वारा संधि की शर्तों का खुला उल्लंघन कर गठित किया गया था।

प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात की

बिश्केक, 31 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को यहां शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से इतर, ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात की।

दोनों नेताओं ने भारत-ईरान संबंधों के साथ-साथ पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम और तेजी से बदलती क्षेत्रीय स्थिति पर बात की।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त करते हुए भारत के इस निरंतर रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए।

एससीओ शिखर सम्मेलनः दुनिया की निगाह मोदी, शी व पुतिन पर

बिश्केक, 31 अगस्त। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन से पहले, सोमवार को चीन के

■ यह बैठक वैश्विक कूटनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत कई देशों के शीर्ष नेता जुटे हैं। पश्चिमी देशों के साथ कई सदस्य देशों के रिश्तों में बढ़ते तनाव के बीच हो रही यह बैठक वैश्विक कूटनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

ओबीसी का मुद्दा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हटाने की मांग से जोड़ रही है।

राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को "भारत का एक्स-रे" बताया है- एक बुनियादी आंकड़ा जुटाने की प्रक्रिया, न कि महज चुनावी मुद्दा। उनका तर्क है कि जिन समुदायों की कभी ठीक से गिनती ही नहीं हुई, उनके लिए प्रभावी नीतियां कैसे बनाई जा सकती हैं।

भाजपा ने इसका जोरदार जवाब देते हुए कांग्रेस को ओबीसी विरोधी और आरक्षण विरोधी करार दिया है। भाजपा के प्रवक्ताओं ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी नेतृत्व को आगे बढ़ाने के पार्टी के रिकॉर्ड का हवाला दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पिछड़ी जाति की पहचान भी शामिल है। उन्होंने राहुल गांधी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हुए कहा है कि राजीव गांधी ने 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था।

ओबीसी समर्थन ने 2014 और 2019 में रिकॉर्ड जनादेश के साथ भाजपा सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन् 2019 में 2014 की तुलना में ऊपरी ओबीसी और निचली जातियों में का समर्थन लगभग दोगुना हो गया था। इसका नुकसान कांग्रेस के साथ-साथ, अन्य क्षेत्रीय एवं छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को भी हुआ।

लेकिन, 2024 में भाजपा को ऊपरी ओबीसी वर्ग में 2 प्रतिशत समर्थन का नुकसान हुआ, जबकि निचली ओबीसी जातियों से लगभग उतना ही समर्थन बढ़ा। दूसरी ओर, कांग्रेस को ऊपरी ओबीसी वर्ग से 5 प्रतिशत और निचली जातियों से 8 प्रतिशत समर्थन मिला। कांग्रेस ने यह बढ़त अपने "संविधान खतरे में है", अभियान और जातीय जनगणना के मुद्दे के आधार पर हासिल की।

पीटीआई भर्ती फ़र्ज़ीवाड़े में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

■ याचिकाकर्ता का आरोप है कि, पूर्व में राज्य सरकार ने आदेश जारी किए थे कि जिन-जिन अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, लेकिन जिनके प्रकरण जांच में लंबित हैं, उन्हें स्थायी नहीं किया जायेगा। परंतु अब कुछ दस्तावेज सामने आए हैं कि इन विवादित अभ्यर्थियों में से भी कुछ लोगों को स्थायी कर दिया गया है।

सरकार के कार्यकाल में हुई भर्तियों के फर्जीवाड़े का यह एक और बड़ा मामला है।

याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया था कि एस.ओ.जी. ने 10 जून 2024 को इस मामले की जांच करते हुए एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें साफ लिखा था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से फर्जी डिग्रियां लेकर नौकरी हासिल की गई है। इनमें से 145 अयोग्य अभ्यर्थियों के पास ओ.पी.जे.एस. यूनिवर्सिटी की डिग्री थी, जबकि अंतिम सूची में मात्र 6 ऐसे योग्य अभ्यर्थी थे, जिनके पास इस यूनिवर्सिटी की डिग्री थी। करीब 173 ऐसे अयोग्य अभ्यर्थी थे, जिन्होंने परीक्षा के बाद डिग्रियां ली थी। कुछ लोग ऐसे थे, जिनके पास ऐसी युनिवर्सिटी की डिग्रियां थीं, जो कि एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी। इसी प्रकार 183 अयोग्य अभ्यर्थी ऐसे थे, जिनके पास अपनी बी.पी.एड. डिग्री में 45 प्रतिशत से भी कम अंक आए थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि 1259 अयोग्य अभ्यर्थियों को शारीरिक शिक्षक पद पर नियुक्ति दी गई है। इनमें से 1230 लोग ऐसे हैं, जिनके आवेदन और डिग्रियां में अंक प्रतिशत व रोल नंबर की गड़बड़ियां हैं। याचिका में कहा गया कि एस.ओ.जी. की इस जांच रिपोर्ट को भी लागू किया जाए। इससे स्पष्ट दिख रहा है कि 2000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़े से नौकरी पायी है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी खुद माना है कि करीब 1502 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिनके दस्तावेज सत्यापन में धांधली पाई गई है। इनमें से 1259 अभ्यर्थियों का डेटा पूरी तरह से मेल नहीं खा रहा है। इसके बावजूद, 1502 लोगों को नियुक्तियां दी गई हैं।

याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2024 में हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में मैरिट लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें 39741 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परंतु पी.टी.आई. भर्ती में 2000 लोगों को बिना मैरिट लिस्ट जारी किए ही सीधे चयनित मान लिया और नियुक्तियां दे दीं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि पूर्व में राज्य सरकार ने आदेश जारी किए थे कि जिन-जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी हैं और उनका प्रकरण जांच में लंबित हैं, उन्हें स्थायी नहीं किया जायेगा। परंतु अब कुछ दस्तावेज सामने आए हैं कि इन विवादित अभ्यर्थियों में से भी कुछ लोगों को स्थायी कर दिया गया है।

भीलवाड़ा में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आवश्यक एवं रीप्लेनिशमेंट स्टडी के अभाव और कृषि भूमि के निकट खनन के भी आरोप लगाए गए हैं। साथ ह, भूजल स्तर में करीब 20 से 30 फीट की गिरावट और गांवों में कुओं के सूखने का दावा किया गया है। एनजीटी ने मामले में जिला कलेक्टर भीलवाड़ा, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, राजस्थान तथा निदेशक खान एवं भू-विज्ञान विभाग को प्रतिवादी बनाया है। अधिकरण ने एक समिति गठित कर मौके का निरीक्षण करने और छह सप्ताह में तथ्यात्मक एवं की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल को समिति के समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। जांच समिति की रिपोर्ट के बाद, मामले में उठाए गए आरोपों की स्थिति और स्पष्ट होगी।

तेहरान का आंतरिक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक अन्य नरमपंथी समर्थक, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची रहे हैं, जिन्होंने कभी-कभार कट्टरपंथी रुख अपनाने के बावजूद, संयमित कूटनीतिक रास्ते का पालन किया है। वे विरोधी पक्षों के बीच चल रही बातचीत में सक्रिय रहे हैं और दोनों देशों के बीच अस्थायी शांति समझौते का मसौदा तैयार करने में उनकी प्रभावशाली भूमिका रही है।

हालांकि, डॉनल्ड ट्रंप के लगातार बदलते और अप्रत्याशित बयानों और, उससे भी अधिक, उनके गैर-जिम्मेदाराना कदमों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, जिसमें ईरान के कट्टरपंथी, नरमपंथियों और समझदार आवाजों के खिलाफ अपनी राजनीति का खेल खेल सकते हैं। अमेरिका के थिंक टैंक में मौजूद मध्य-पूर्व के कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर डॉनल्ड ट्रंप ने अचानक अपना रुख नहीं बदला होता और वे भरोसेमंद होते तो शांति समझौता सफल हो सकता था। ट्रंप की सबसे बड़ी गलती ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को सीमित करने वाले बहुराष्ट्रीय समझौते को पूरी तरह खारिज करना था। इसके बाद से डॉनल्ड ट्रंप उस बहुराष्ट्रीय समझौते की कामयाबी के आसपास भी नहीं पहुंच सके हैं और ईरान को जेसीपीओए समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियों से बच निकलने का रास्ता मिल गया है।

अब ऐसा लगता है कि दबाव में आकर डॉनल्ड ट्रंप जेसीपीओए समझौते से कमतर स्तर के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान से कोई समझौता स्वीकार कर सकते हैं। यह डॉनल्ड ट्रंप की अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रति व्यक्तिगत नापसंदगी और दुश्मनी तथा ईरानियों के साथ बातचीत के प्रति उनका गैर-पेशेवर रवैये का नतीजा था।

ट्रंप ने अमेरिकी विदेश विभाग के सभी पेशेवर अधिकारियों को किनारे कर दिया और अपने उस प्रॉपर्टी डेवलपर मित्र तथा दामाद पर भरोसा किया, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने समझौते के मसौदों में मूर्खतापूर्ण गलतियां कीं और ऐसी शर्तें रखीं, जिनका ईरानियों ने फायदा उठाया।

इस तरह, ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में व्यावहारिक सोच रखने वाले नेताओं और कट्टरपंथियों के बीच सत्ता के लिए चल रही जबरदस्त खींचतान, अमेरिका के साथ युद्ध को लंबा खींच रही है, जिसकी भारी कीमत ईरान की जनता को चुकानी पड़ रही है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा। आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, क